RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 27 MAY TO 02 JUNE 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 40 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

शेयर बाजार में भारी तेजी, सेंसेक्स 996 अंक बढ़कर बंद
Page 2

आरोग्य सेतु ऐप में खामी ढूंढने वाले को बड़ा इनाम देगी सरकार
Page 4

टिड्डी दल : कोरोना वायरस के बाद अब भारत पर एक और हमला!
Page 7

editoria!

फिर चमकेंगे बाजार

कोरोना और लॉकडाउन से पैदा हुई असामान्य स्थितियों ने पहले से ही लड़खड़ा रही भारतीय अर्थव्यवस्था का बुरा हाल कर दिया है। इसकी झलक बीते सप्ताह रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास की घोषणाओं में भी देखी जा सकती है। लगातार नीचे आ रही रेपो रेट को एक बार फिर घटाकर उन्होंने चार फीसदी पर ला दिया जो साल 2000 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को रिजर्व बैंक से कर्ज मिलता है। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों से लिए गए कर्जों की किस्त चुकाने पर मिली छूट की अवधि तीन महीने और बढ़ाकर अगस्त तक कर दी। अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियों की गंभीरता का संकेत करते हुए उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस साल जीडीपी बढ़ोतरी के आंकड़े नेगेटिव रह सकते हैं। यह साफगोई इस लिहाज से अच्छी है कि जब देश एक आपदा से गुजर रहा हो तब देशवासियों को किसी गफलत में नहीं रहना चाहिए। मगर सचाई यह भी है कि एक सीमा के बाद न सिर्फ देशवासियों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी जीडीपी के आंकड़ों का खास मतलब नहीं रह जाता। ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि किन-किन सेक्टरों में कितनी कंपनियां खड़ी रह पाएंगी, कितनी दुकानें खुली रह सकेंगी और अंततः कितने लोगों का रोजगार बचाए रखना संभव होगा। इस दृष्टि से सीमित ही सही, पर पहली दोनों घोषणाएं उपयोगी हो सकती हैं। रेपो रेट में कटौती से बाजार में लिक्विडिटी बनी रहेगी तो कम से कम कैश की कमी कोई मुद्दा नहीं बनेगी। रहा सवाल सस्ते कर्ज से इकॉनमी में हरकत लाने का तो जब बाजार में मांग ही नदारद है तो कंपनियां कर्ज लेकर अपना उत्पादन आखिर किसके लिए बढ़ाएंगी? कर्ज की किस्त चुकाने पर कुछ और महीनों की छूट ज्यादा राहत देने वाली इसलिए नहीं लगती क्योंकि कर्जा तो ज्यों का त्यों वापस करना ही है। इधर की छूटी हुई सारी किस्तें जमा होती जाएंगी और राहत का दौर खत्म होने के बाद इस अवधि का भी सूद जोड़कर वसूल की जाएंगी। ऐसे में एक आशंका यह भी बनती है कि अदायगी शुरू होते ही बैंकों को अचानक डिफॉल्टरों की संख्या में भारी इजाफा न झेलना पड़े। बहरहाल, तमाम खतरों के बावजूद ये छूटें अनुपयोगी या अनावश्यक नहीं हैं। जो कारोबारी इन रियायतों का ढंग से इस्तेमाल करते हुए अपने कर्मचारियों और ग्राहकों से भरोसे का रिश्ता जोड़े रहेंगे, उनमें से बहुतों के लिए ये संजीवनी का काम कर सकती हैं। बिजनेस सेंस आखिर बदलती स्थितियों से जुड़ी जरूरतों को समय रहते भांपने और उसी के अनुरूप अपने रंग-रूप और तेवर बदलने का ही दूसरा नाम है । बड़ी से बड़ी त्रासदी, बड़ा से बड़ा संकट, खतरनाक से खतरनाक महामारी भी इंसानी जिजीविषा के इस पहलू को मात नहीं दे सकती। लॉकडाउन आंशिक रूप से खुलने के साथ ही भारतीय बाजारों में हलचल शुरू हो गई है। उम्मीद है कि अगले एक-दो महीनों में ही इनकी जगमगाहट फिर पहले जैसी हो जाएगी।

कोरोना संकट से दोगुना होगा बैंकों का NPA
1.5 लाख करोड़ डालने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली। एजेंसी

बैंकिंग सेक्टर का हाल पहले से ही काफी बुरा था, लेकिन कोरोना के कारण बैड लोन में भारी इजाफा होने की पूरी संभावना है, सरकार भी इस बात को भली भांति जानती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के बाद बैंकों से लगातार कह रही हैं कि वे लोन बांटने में दिक्कत ना करें और याद रखें कि इसकी गारंटी सरकार दे रही है। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बैंकों की माली हालत को देखते हुए इस सेक्टर में 20 अरब डॉलर (करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये) डालने की जरूरत है।

बैड लोन का बोझ दोगुना होने की पूरी संभावना

माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण बैंकों पर बैड लोन का बोझ लगभग दोगुना होने वाला है। एक सूत्र के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कहा कि पहले सरकार 25 हजार करोड़ रुपये का स्पेशल बजट बैंक री-कैपिटलाइजेशन के बारे में सोच रही थी। लेकिन कोरोना संकट इतना गंभीर है कि इसे अब काफी आगे बढ़ा दिया गया है।

बैंकों को फ्रेश फंड की जरूरत

डिमांड में तेजी लाने के लिए रिजर्व बैंक लगातार रीपो रेट घटा रहा है और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए साथ ही साथ रिवर्स रीपो रेट में कटौती की जा रही है। वर्तमान हालात में बैंकों को फ्रेश फंड की सख्त जरूरत है।

दूसरी छमाही में फैसला संभव

एक दूसरे सूत्र ने कहा कि कैपिटलाइजेशन का प्लान अभी ठंडे बस्ते में नहीं गया है। संभव है कि सरकार इस दिशा में वित्त वर्ष की दूसरी छमाही अक्टूबर-मार्च में विचार करे। पिछले दिनों वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा था कि अभी तक जो कदम उठाए गए हैं, वह वर्तमान परिस्थिति को लेकर है। जरूरत के हिसाब से आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण कदम उठाएं जाएंगे। सरकार पूरी गंभीरत से इस दिशा में विचार कर रही है।

सितंबर 2019 में 9.35 लाख करोड़ का NPA

बैंकों के एनपीए की बात करें तो सितंबर 2019 में बैंकों का कुल एनपीए करीब 9.35 लाख करोड़ रुपये था। उस समय यह उनके कुल असेट का 9.1 फीसदी के करीब था। पिछले दिनों रॉयटर्स ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि कोरोना महामारी के कारण बैड लोन का बोझ उनके कुल असेट का 18-20 फीसदी तक पहुंच सकता है।

जीडीपी घटने का पूरा अनुमान

पूरे देश में करीब दो महीने से लॉकडाउन की स्थिति है जिसके कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। लाखों लोग बेरोजगार भी हुए हैं। तमाम रेटिंग एजेंसियों का कहना है कि जीडीपी में 5 फीसदी या उससे ज्यादा तक की गिरावट आ सकती है।

किस तरह होगा री-कैपिटलाइजेशन?

री-कैपिटलाइजेशन को लेकर सूत्रों का कहना है कि अकेले सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह इतना ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूज करे। संभव है कि इसके लिए बॉन्ड जारी किए जाएं, जो पूर्व में भी किए गए हैं। इसके अलावा कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक फिस्कल डेफिसिट मोनेटाइजेशन के जरिए भी कर सकता है।

लेंडिंग स्पीड में नहीं आए कमी

पिछले पांच सालों में सरकार की तरफ से पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए पहले ही 3.5 लाख करोड़ रुपये की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की जा चुकी है। बजट 2020-21 में कैपिटल इन्फ्यूजन का कहीं जिक्र नहीं किया गया था। कोरोना काल में लोन बांटने की स्पीड जरूर कम हुई है, लेकिन सरकार चाहती है कि संकट के कारण इस पर असर ना हो और बैंक की लेंडिंग स्पीड 6-7 फीसदी की दर से बढ़ती रहे।

इंडस्ट्रीज पूरी रफ्तार से नहीं चल रही, फिर भी इस बार टूट जाएंगे बिजली की डिमांड के सारे रेकॉर्ड?

नई दिल्ली। एजेंसी

लॉकडाउन के चौथे चरण में इंडस्ट्रीज चलाने की छूट मिलने और तामपान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद दिल्ली में बिजली की डिमांड बढ़ने लगी है। सोमवार को दिल्ली में 5,100 मेगावॉट से अधिक पावर डिमांड रही। इसके पहले रविवार को डिमांड 5,268 मेगावॉट थी। यह हाल तब है, जब इंडस्ट्रीज पूरी रफ्तार से नहीं चल रही हैं।

ऐसी ही रही गर्मी तो टूटेंगे और रेकॉर्ड

बिजली कंपनियों का कहना है कि सभी इंडस्ट्रीज पूरी तरह से चालू हो जाएं और इसी तरह से तापमान और कुछ दिनों तक बना रहे, तो डिमांड में 6000 मेगावॉट से भी ज्यादा होगी। पिछले साल का अधिकतम डिमांड 7409 मेगावॉट का रेकॉर्ड भी टूट सकता है।

इंडस्ट्रीज की रफ्तार के हिसाब से बढ़ती है डिमांड, पर इस बार अधिकारियों का कहना है कि इंडस्ट्रीज के पूरी तरह से रफ्तार पकड़ने के बाद ही दिल्ली में अधिक पावर डिमांड होती है। लेकिन, इस बार तापमान ज्यादा होने के कारण डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। कुछ दिन पहले तक गर्मी ज्यादा नहीं थी, तो डिमांड भी कम थी। पिछले साल की तुलना में भी डिमांड कम थी।

24 मई को रही सबसे ज्यादा डिमांड

पिछले साल जब दिल्ली में इंडस्ट्रीज पूरी तरह से चल रही थी, तब 15 मई को दिल्ली में 5,172 मेगावॉट डिमांड दर्ज की गई थी। इस साल इस दिन सिर्फ 3,698 मेगावॉट ही डिमांड रही। 21 मई तक पिछले साल की तुलना में पावर डिमांड कम थी। इसके बाद तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और पावर डिमांड में भी बढ़ोतरी हुई। 24 मई को सबसे अधिक 5,200 मेगावॉट पावर डिमांड रेकॉर्ड की गई।

जीएसटी पर आपदा उपकर लगाने पर विचार नहीं - वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वित्त मंत्रालय वस्तु एवं सेवा कर पर आपदा उपकर लगाने पर विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनियों को पहले से ही बिक्री में गिरावट और मांग में कमी का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले कुछ खबरों में कहा गया था कि केंद्र सरकार जीएसटी पर उसकी तरह का आपदा उपकर लगाने पर विचार कर रही है, जैसा केरल सरकार ने पिछले साल जून में बाढ़ उपकर लगाया था। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में किसी भी प्रकार का आपदा उपकर लगाना अपने-आप में एक आपदा से कम नहीं होगा। एक सूत्र ने कहा कि इस समय इस प्रकार कर बढ़ाने से उल्टे नुकसान ही होगा क्योंकि बिक्री पहले से ही कम है और उद्योग जगत मांग में गिरावट और मजदूरों को लेकर कठिनाइयों का सामना कर रहा है।

सूत्र ने कहा, 'इस तरह के किसी भी उपाय से उपभोक्ताओं का हौसला गिर सकता है और बाजार कमजोर हो सकता है, खासकर तब जब सरकार उपभोग को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही है।' अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी किसी भी देश ने इस महामारी समय के दौरान इस तरह का प्रयोग नहीं किया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इससे पहले दिन में ट्वीट किया था, 'यहां तक कि आरबीआई ने भी माना है कि इस साल वृद्धि दर नकारात्मक रहने वाली है। ऐसे में जीएसटी पर आपदा उपकर लगाने के बारे में सोचिए भी मत। यह एक अन्य आपदा साबित होगा।

सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ाई BPCL की बोली की समयसीमा

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के निजीकरण के लिए बोली की समयसीमा को दूसरी बार बढ़ा दिया है। एक आधिकारिक नोटिस के अनुसार, रुचि पत्र जमा करने की अंतिम तारीख एक महीने से अधिक बढ़ाकर 13 जून की जगह 31 जुलाई कर दी गई है।

नवंबर में मिली थी हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी

मालूम हो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में बीपीसीएल में सरकार की पूरी 52.98 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद सात मार्च को हिस्सेदारी खरीदने में रुचि रखने वालों से रुचि पत्र (ईओआई) मांगे गए थे। ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि दो मई थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 13 जून तक कर दिया गया।

इस संदर्भ में सरकार ने बुधवार को कहा कि इस समयसीमा को आगे 31 जुलाई तक बढ़ाया जा रहा है। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने एक नोटिस में कहा कि, 'इच्छुक बोलीदाताओं के अनुरोधों और कोविड-19 से पैदा हुई मौजूदा स्थिति के मद्देनजर प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) पर लिखित पूछताछ की अंतिम तिथि एक बार फिर 23 जून 2020 तक बढ़ाई गई है और ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया गया है।'

खरीदार को दिया जाएगा प्रबंधन नियंत्रण

भारत सरकार ने बीपीसीएल में अपनी पूरी हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव किया है, जिसमें 114.91 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं, जो बीपीसीएल की इक्विटी शेयर पूंजी का 52.98 फीसदी हिस्सा है। इसके तहत रणनीतिक खरीदार को प्रबंधन नियंत्रण भी दिया जाएगा। हालांकि, इस बिक्री में बीपीसीएल की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में 61.65 फीसदी हिस्सेदारी शामिल नहीं है।

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की एक तेल और गैस कंपनी को बेची जाएगी। बोली दो चरणों में होगी, जिसके तहत पहले आईओआई चरण के योग्य बोलीदाताओं से दूसरी चरण में वित्तीय बोली लगाने के लिए कहा जाएगा। पेशकश दस्तावेज में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) इस बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं।

लॉकडाउन 4 में पेट्रोल- डीजल की मांग में हुआ इजाफा, जल्द बढ़ सकते हैं दाम

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोनावायरस महामारी का प्रकोप देश में बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के चलते आर्थिक समस्याएं भी बढ़ गई हैं। इनमें सरकार को मिलने वाला राजस्व भी शामिल है। ऐसे में जानकारों का अनुमान है कि सरकार राजस्व को बढ़ाने एक बार फिर से पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर सकती है। मालूम हो कि लॉकडाउन 3 में कई राज्य सरकारों ने अपने खजाने को खाली होता देख ईंधन पर वैट बढ़ाया था, जिसके चलते संबंधित राज्यों में पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है।

वहीं अब एक ओर जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल नजर आने लगा है। वहीं दूसरी ओर देश में लॉकडाउन 4 में दी गई छूट के चलते पेट्रोल- डीजल की मांग में भी इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट की मानें तो मई माह के अंत या अगले माह में भारतीय तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर सकती हैं। फिलहाल बात करें आज (बुधवार 27 मई) की तो पेट्रोल-डीजल के दाम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है।

ऐसे तय होती है कीमत

विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करती हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की दरों में संशोधन कर जारी करती हैं।

ऐसे जानें अपने शहर में ईंधन की कीमत

पेट्रोल-डीजल की रोज की कीमतों की जानकारी आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल के उपभोक्ता को RSP लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। वहीं बीपीसीएल उपभोक्ता को RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेजना होगा, जबकि एचपीसीएल उपभोक्ता को HPPrice लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजना होगा, जिसके बाद ईंधन की कीमत की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अप्रैल में घटा आयात, पर रिफाइंड प्रोडक्ट का निर्यात बढ़ा

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अप्रैल में भारत के कच्चे तेल के आयात में साल दर साल आधार पर 10 महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दरअसल कोरोनोवायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां ठप्प हो गईं, जिससे मांग में कमी आई। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में कच्चे तेल का आयात एक साल पहले की तुलना में 12.4 प्रतिशत घटकर 17.28 मिलियन टन रह गया, जो कि जून 2019 से आई सबसे बड़ी गिरावट है। तेल उत्पादों का आयात भी 6.5 फीसदी घटकर 3.35 मिलियन टन रह गया। इसमें साल दर साल आधार पर पिछले 16 महीनों में पहली बार गिरावट आई है। अप्रैल में ईंधन की मांग भी 45 फीसदी से अधिक गिर गई। इसकी वजह भी लॉकडाउन से औद्योगिक गतिविधियों का बंद होना है।रिफाइंड उत्पादों का निर्यात बढ़ा घरेलू मांग में भारी गिरावट के कारण अक्टूबर 2016 के बाद से रिफाइंड उत्पादों के निर्यात में साल-दर-साल आधार पर सबसे अधिक वृद्धि हुई। दरअसल भारतीय रिफाइनर्स पूरी तरह कारोबार बंद करने से बचने के लिए रिफाइंड ईंधन का निर्यात करते रहे। रिफाइंड उत्पादों का निर्यात एक साल पहले की तुलना में 37 प्रतिशत बढ़ कर 6.04 मिलियन रहा। इनमें डीजल का निर्यात, जो एक्सपोर्ट का प्रमुख हिस्सा है, अप्रैल में साल दर साल आधार पर 68 प्रतिशत बढ़कर 3.40 मिलियन टन रहा।

घटेगी पेट्रोलियम उत्पादों की मांग इस बीच इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) ने अपनी मई तेल मार्केट रिपोर्ट में कहा है कि भारत की पेट्रोलियम उत्पाद की माँग 2020 में आठ प्रतिशत घट कर 4,597 हज़ार बैरल प्रति दिन (केबीडी) रह जाएगी। वहीं रिपोर्ट में 2020 की पहली तिमाही पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले में तेल की मांग 180 केबीडी और दूसरी तिमाही में 1.3 मिलियन बैरल प्रति दिन गिरने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल की अंतिम तिमाही में खपत अपने एक साल पुराने लेवल पर आ सकेगी। पेट्रोल की मांग भी घटेगी दूसरी तिमाही में पेट्रोल की मांग 350 केबीडी और डीजल की मांग 690 केबीडी गिरने का अनुमान है। कुल मिला कर 2020 में भारत की तेल की मांग गिर कर 4.60 मिलियन बैरल प्रति दिन रहने का अंदाजा लगाया गया है, जो 2019 में 5.01 मिलियन बैरल प्रति दिन रही थी। एजेंसी को उम्मीद है कि 2020 में भारत के घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में भी गिरावट जारी रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले महीनों में कच्चे तेल का उत्पादन कम रहेगा और 2020 में 0.75 मिलियन बैरल प्रति दिन तक गिर सकता है, जो 2019 0.80 मिलियन बैरल प्रति दिन दर्ज किया गया था।

शेयर बाजार में भारी तेजी, सेंसेक्स 996 अंक बढ़कर बंद

मुम्बई। आईपीटी नेटवर्क

आज बुधवार यानी 27 मई 2020 को शेयर बाजार भारी तेजी के साथ बंद हुआ। आज जहां सेंसेक्स करीब 996 अंक की तेजी के साथ 31,605 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 286 अंक की तेजी के साथ 9315 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा आज बीएसई में कुल 2477 कंपनियों में ट्रेडिंग हुई, इसमें से करीब 1351 शेयर तेजी के साथ और 956 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं 170 कंपनियों के शेयर के दाम में कोई अंतर नहीं आया। वहीं आज शाम को डॉलर के खिलाफ रुपया 6 पैसे की कमजोरी के साथ 75.72 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार 2 महीने के ऊपरी स्तर पर शेयर बाजार आज 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 1 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में आज 2 महीने में सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला। बैंक निफ्टी 1270 अंक चढ़कर 18,711 पर बंद हुआ है। मिडकैप 76 अंक चढ़कर 12,911 पर बंद हुआ है। फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी रही। निफ्टी के टॉप गेनर एक्सिस बैंक का शेयर करीब 46 रुपये की तेजी के साथ 387.00 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर करीब 26 रुपये की तेजी के साथ 318.85 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। विप्रो का शेयर करीब 12 रुपये की तेजी के साथ 201.25 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। ग्रेसिम का शेयर करीब 34 रुपये की तेजी के साथ 566.65 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 51 रुपये की तेजी के साथ 903.65 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के टॉप लूजर सन फार्मा का शेयर करीब 8 रुपये की गिरावट के साथ 450.90 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर करीब 59 रुपये 59 रुपये की गिरावट के साथ 3,727.40 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। श्री सीमेंट का शेयर करीब 190 रुपये की गिरावट के साथ 20,477.55 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। टाइटन कंपनी का शेयर करीब 7 रुपये की गिरावट के साथ 885.85 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। एशियन पेंट्स का शेयर करीब 10 रुपये की गिरावट के साथ 1,619.45 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया पांच पैसे की गिरावट के साथ 75.71 पर बंद

मुंबई। एजेंसी

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार को पांच पैसे की गिरावट के साथ 75.71 (अस्थायी) बंद हुआ। कोरोना वायरस महामारी के बीच अमेरिका और चीन के मध्य तनाव बढ़ने को लेकर प्रतिभागी चिंतित हैं। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार रुपया सीमित दायरे में रहा। कोरोना वायरस टीका आने की संभावना और व्यापार गतिविधियों में तेजी की उम्मीद से रुपया कुछ मजबूत हुआ। लेकिन अमेरिका-चीन क बीच तनाव बढ़ने से तेजी पर अंकुश लगा। विश्व की अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मजबूत होने से भी रुपये पर असर पड़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 75.72 पर खुला। बाद में कुछ मजबूत हुआ लेकिन अंत में यह मंगलवार के मुकाबले पांच पैसे की गिरावट के साथ 75.71 पर बंद हुआ। रुपया मंगलवार को 75.66 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह ऊंचे में 75.57 और नीचे में 75.74 तक गया। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध (मुद्रा) प्रमुख राहुल गुप्ता ने कहा, ''अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वह चीन के हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय थोपने के खिलाफ हैं। कोरोना वायरस संकट से वैश्विक वृद्धि पर पहले से असर है। अब इन दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होने का और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।''

अप्रैल में भारत का क्रूड इस्पात उत्पादन 65 प्रतिशत गिरकर 31.3 लाख टन रहा: वर्ल्डस्टील

नयी दिल्ली। अप्रैल महीने में भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन 65 प्रतिशत से अधिक घटकर 31.3 लाख टन पर आ गया। विश्व इस्पात संघ ने इसकी जानकारी दी है। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिये देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। इसने भारत में इस्पात के उत्पादन, मांग और आपूर्ति को प्रभावित किया है। विश्व इस्पात संघ (वर्ल्डस्टील) ने एक रिपोर्ट में कहा कि एक साल पहले इसी महीने (अप्रैल 2019) के दौरान देश में 90.2 लाख टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ था। इससे पहले मार्च 2020 में कच्चा इस्पात उत्पादन मार्च 2019 के 100.4 लाख टन की तुलना में 14 प्रतिशत

कम होकर 86.5 लाख टन रहा था। अप्रैल महीने के दौरान वैश्विक स्तर पर इस्पात के उत्पादन में 13 प्रतिशत की गिरावट रही और यह अप्रैल 2019 के 1,576.7 लाख टन की तुलना में कम होकर अप्रैल 2020 में 1,370.9 लाख टन पर आ गया। वर्ल्ड स्टील ने कहा, 'कोविड-19 महामारी के कारण आ रही कठिनाइयों को लेकर इस महीने के कई आंकड़े अनुमानित हैं, जिन्हें अगले महीने के उत्पादन अपडेट के साथ संशोधित किया जा सकता है।' चीन के इस्पात उत्पादन में पिछले कई महीनों के दौरान पहली बार मार्च में 1.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी और यह 789.7 लाख टन रहा। चीन ने अप्रैल में 850.3 लाख टन इस्पात का उत्पादन किया। यह साल भर पहले के समान माह की तुलना में 0.2 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान अमेरिका में उत्पादन 32 प्रतिशत गिरकर 49.6 लाख टन, जापान में 23 प्रतिशत गिरकर 66.1 लाख टन, दक्षिण कोरिया में 8.4 प्रतिशत गिरकर 55 लाख टन, जर्मनी में 10.7 प्रतिशत गिरकर 30 लाख टन, इटली में 30.7 प्रतिशत गिरकर 13.5 लाख टन, फ्रांस में 37.9 प्रतिशत गिरकर आठ लाख टन और स्पेन में 48 प्रतिशत कम होकर 6.7 लाख टन पर आ गया। इनके अलावा अप्रैल में रूस ने 47 लाख टन कच्चे इस्पात के उत्पादन का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान यूक्रेन में 13.3 लाख टन, ब्राजील में 18.1 लाख टन और तुर्की में 22.4 लाख टन कच्चा इस्पात उत्पादन हुआ।

LPG सिलेंडर में सालों में पहली बार सब्सिडी हुई शून्य

जानिए कैसे हुआ ऐसा

नई दिल्ली। एजेंसी

LPG सिलेंडर के मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर है। साथ ही उपभोक्ताओं को भी खुशी मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट के कारण ऐसा हुआ है। सरकार को इतनी सस्ती एलपीजी मिल रही है कि उसे अब घरेलू बाजार में अपने उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी पर मई महीने के दौरान कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। यानी अब श्ज्ञ सिलेंडर सब्सिडी शून्य पर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, इसी महीने सरकार सब्सिडी देने के बाद भी एक सिलेंडर पर 120 रुपए की कमाई शुरू कर देगी। यह सब इसलिए हो सका है क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ महीनों में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैर-सब्सिडी सिलेंडर पर अच्छे खासे दाम बढ़ाकर रखे थे। यानी एक तरफ तो सरकार ने दाम बढ़ाए थे और दूसरी तरह उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ते दाम में गैस मिल रही है। सब्सिडी शून्य हो गई और सरकार की पौ बारह। मालूम हो, जनवरी 2015 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की शुरुआत की गई थी। इसके तहत उपभोक्ता बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर एलपीजी सिलेंडरों की पूरी (बाजार) कीमत चुका रहे हैं। वहीं, सरकार सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खातों में जमा कराती है। पारदर्शी मूल्य निर्धारण के लिए यह व्यवस्था की गई थी।

इससे पहले थी यह व्यवस्था

इससे पहले तेल विपणन कंपनियां उपभोक्ताओं को लागत से कम कीमत पर सिलेंडर बेचती थीं और फिर सरकार उनके नुकसान

की भरपाई करती थी। हालांकि सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए अक्टूबर 2017 और जुलाई 2019 के बीच गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत को स्थिर कर दिया। इसकी वजह थी सरकार की पीएम उज्ज्वला योजना। सरकार ने गरीबों में रसोई गैस के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए 1,600 रुपए की नकद सहायता प्रदान की। इसका मतलब यह था कि एलपीजी सिलेंडर की पूरी कीमत वास्तव में लागत से भी कम थी।

भारत गैस के कस्टमर्स हैं? इस तरह वॉट्सऐप से करें बुकिंग

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए तमाम कंपनियां टेक्नॉलजी का ज्यादा से ज्यादा और बेहतर इस्तेमाल कर रही हैं। भारत गैस ने अपने एलपीजी गैस सिलिंडर कस्टमर्स के लिए वॉट्सऐप के जरिए बुकिंग करने की सुविधा शुरू की है। अगर आप भारत गैस (BPCL) के कस्टमर्स हैं तो 27 मई से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए गैस की बुकिंग कर सकते हैं।

पूरे देश में 7 करोड़ है कस्टमर्स

पूरे देश में भारत गैस के करीब 7 करोड़ कस्टमर्स हैं। अपने इन कस्टमर्स के लिए कंपनी ने वॉट्सऐप बिजनस चैनल की शुरुआत की है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि इससे उन्हें गैस बुकिंग में आसानी होगी और वे परेशानी से भी बचेंगे।

रिफील के लिए प्रीपेड ऑनलाइन पेमेंट भी

कंपनी के एग्जिक्युटिव डायरेक्टर (LPG) टी पिताम्बरम ने कहा कि वॉट्सऐप का इस्तेमाल हर उम्र के लोग कर रहे हैं। ऐसे में

इस सुविधा को शुरू करने से हम अपने कस्टमर्स के साथ बेहतर जुड़ पाएंगे। कस्टमर्स को वॉट्सऐप मैसेज के जरिए एक लिंक शेयर की जाएगी, जिसकी मदद से वे रिफील के लिए प्रीपेड ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं।

कैसे करनी है बुकिंग?

भारत गैस ने BPCL स्मार्टलाइन नंबर -1800224344 जारी किया है। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज करना है 'Hi'. उसके बाद टाइप करना है 'Book' या '1' फिर उसे भेज देना है। इससे आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी और कंफर्मेशन मैसेज भी मोबाइल पर आ जाएगा।,रर

लॉकडाउन बढ़ाने से अर्थव्यवस्था के साथ स्वास्थ्य संकट का जोखिम: आनंद महिंद्रा

नई दिल्ली। एजेंसी

सोशल मीडिया पर मुखर होकर अपनी बात कहने वाले महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने लॉकडाउन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाना न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा, बल्कि यह एक नया स्वास्थ्य संकट भी पैदा करेगा। महिंद्रा ने ट्वीट किया, ''लॉकडाउन को आगे बढ़ाना न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा। बल्कि जैसा कि मैंने पहले भी ट्वीट कर कहा है कि यह एक अन्य स्वास्थ्य संकट को पैदा करने वाला होगा।'' उन्होंने 'लॉकडाउन के खतरनाक मनोवैज्ञानिक प्रभाव और कोविड-19 के अलावा अन्य मरीजों की अनदेखी' विषय पर लिखे एक लेख का हवाला दिया। महिंद्रा ने लॉकडाउन के 49 दिन बाद इसे हटाने का प्रस्ताव किया था। उन्होंने कहा, ''नीति निर्माताओं के लिए चयन करना आसान नहीं है, लेकिन लॉकडाउन से भी मदद नहीं मिलने वाली है।' उन्होंने कहा, 'कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी और हमारा पूरा ध्यान तेजी से अस्पताल के बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने पर होना चाहिए।'' महिंद्रा ने इस काम में सेना की मदद लेने के लिए भी कहा, क्योंकि सेना के पास इसका तजुर्बा है।

मैग्मा एच.डी.आई. बीमा कंपनी द्वारा लॉकडाउन के समय में पहल कर मुकदमों का निराकरण

इंदौर। मैग्मा एच.डी.आई. बीमा कंपनी द्वारा इस कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में पहल कर मोटर दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे की राशि, क्लेम प्रकरणों में राजीनामा कर दिलाई गई। इस प्रकिया को कंपनी के उच्च अधिकारी सोमनाथ घोष व करन पुरोहित के निर्देशन में एडविन गार्डिया द्वारा पूर्ण किया गया। मैग्मा एच.डी.आई. बीमा कंपनी द्वारा यह भी बताया गया कि वह इस लॉकडाउन समय में अन्य मुकदमों में राजीनामा करने में जुटी है, ताकि मोटर दुर्घटना में आहत एवं उनके परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा प्राप्त हो सके।

SBI ने एक महीने में दूसरी बार एफडी पर कम कर दिया ब्याज

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय स्टेट बैंक ने एक महीने में दूसरी बार फिक्स डिपॉजिट करने वाले ग्राहकों को झटका दिया है। बैंक ने सावधि जमा पर ब्याज दरों में 40 आधार अंकों की कटौती की है। नई एफडी दरें आज यानी 27 मई से प्रभावी हो गई हैं। एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक बैंक ने 2 करोड़ या इससे अधिक की एफडी पर भी 50 बीपीएस तक की कटौती की है। इस श्रेणी के तहत एसबीआई द्वारा प्रस्तावित ब्याज दर अधिकतम 3% है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली नई दरें भी बुधवार से ही लागू हो गई हैं।

एसबीआई एफडी की लेटेस्ट ब्याज दरें

7 दिन से 45 दिन 2.9%
46 दिन से 179 दिन 3.9%
180 दिन से 210 दिन 4.4%
211 दिन से 1 वर्ष से कम 4.4%
1 वर्ष से 2 वर्ष से कम 5.1%
2 साल से 3 साल से कम 5.1%
3 साल से 5 साल से कम 5.3%
5 साल और 10 साल तक 5.4%

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
हर भारतीय का बैंक
THE BANKER TO EVERY INDIAN

फिच : लॉकडाउन से भारत का बिगड़ा यह साल, लेकिन अगला रहेगा काफी अच्छा

नई दिल्ली। एजेंसीकोरोना महामारी के चलते देश और दुनिया में लागू लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ऐसे में भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देशों की जीडीपी में भारी कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। फिच रेटिंग्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष में बुरी तरह से प्रभावित होगी, लेकिन अगला वित्त वर्ष भारत के लिए काफी अच्छा रहेगा। रेटिंग एजेंसी फिच का अनुमान है भारत की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में 5 फीसदी की गिरावट आ सकती है। इससे पहले अप्रैल में फिच का अनुमान जताया था कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 0.8 प्रतिशत रहेगी। लेकिन अब फिच ने अपने इस अनुमान को और घटा दिया है। हालांकि फिच ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक (जीईओ) में कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22

में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और यह 9.5 फीसदी की ग्रोथ रेट हासिल होगी।

ये है फिच की रिपोर्ट

फिच रेटिंग्स ने जारी किए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक (जीईओ) में कहा कि उसने मई में जो दुनिया की जीडीपी के अनुमान जारी किए थे, उसमें कटौती कर दी है। लेकिन ये भी कहा है कि दुनिया की आर्थिक गतिविधियों में गिरावट थोड़ा-थोड़ा खत्म हो रही है। फिच ने कहा कि सबसे अधिक कटौती भारत की ग्रोथ रेट में की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 फीसदी की भारी गिरावट आएगी। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में 0.8 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। फिच का अनुमान है कि बीते वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की वृद्धि दर 3.9 प्रतिशत रहेगी। हालांकि फिच ने जीईओ में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और यह 9.5 फीसदी की ग्रोथ रेट हासिल कर लेगी। फिच रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट ब्रायन कुल्टन ने कहा है कि साल 2020 में दुनिया की जीडीपी में अब 4.6 फीसदी की गिरावट का अनुमान था। वहीं अप्रैल में इसमें 3.9 फीसदी की गिरावट का अनुमान लगाया गया था। यह यूरोक्षेत्र और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुमान को और घटाने की वजह से है। वहीं भारत में अनुमान से लम्बा लॉकडाउन होने के चलते फिच का अनुमान बदलना पड़ा है।

सीआईआई ने कंपनियों से कहा

प्रतिस्पर्धा कानून का ध्यान रख कर गठंधन-समझौते करें

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ऐसे में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने रविवार को कंपनियों से कहा कि वे कारोबारी गठजोड़ करते समय सतर्कता बरतें, जिससे प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन न हो।अनुचित व्यापार व्यवहार की निगरानी करने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने पहले ही इस बारे में परामर्श जारी करते हुए कहा है कि प्रतिस्पर्धा कानून में पहले से ऐसे 'सेफगार्ड्स' हैं जो कंपनियों को इस तरह के संयोजन के व्यवहार में प्रतिबंधों से संरक्षण देते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि ऐसी गतिविधियों से दक्षता बढ़नी चाहिए। सीसीआई ने कंपनियों को आगाह किया है कि वे कोविड-19 की स्थिति का लाभ उठाकर इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करें। सीआईआई ने इस महामारी के बीच प्रतिस्पर्धा कानून के अनुपालन का 'मैनुअल' पेश किया है। सीसीआई ने कहा कि कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था का कामकाज इतनी बुरी तरह प्रभावित हुए है कि कुछ कंपनियां अनिश्चितता और मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए प्रतिद्वंद्वियों के साथ गठजोड़ कर सकती हैं। सीआईआई ने कहा कि कंपनियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह कानून अब भी लागू है। कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले सभी कारोबारी निर्णय प्रतिस्पर्धा कानून, 2002 के प्रावधानों के अनुकूल होने चाहिए। उद्योग मंडल ने कहा कि इस अवधि के दौरान वह किसी संभावित प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन की निगरानी करेगा। सीआईआई द्वारा जारी मैनुअल में कहा गया है कि कोविड-19 की अवधि के दौरान कंपनियां अपने कारोबारी परिचालन का सावधानी से आकलन करें। विशेषरूप से यह देखते हुए कि उन्हें अपने परिचालन में प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के साथ गठजोड़ करना पड़ सकता है। सीआईआई ने कहा कि सीसीआई ने इस बारे में कोई निर्देशन जारी नहीं किया है, ऐसे में कंपनियां सावधानी बरतें और किसी तरह का गठजोड़ करने से पहले अपने प्रतिस्पर्धा से संबंधित अधिवक्ता से विचार-विमर्श करें।

कोविड-19 से भारत में डिजिटलीकरण बढ़ेगा, इंटरनेट इस्तेमाल बढ़ाने में जियो होगा मददगार: मॉर्गन स्टेनली

नयी दिल्ली। मॉर्गन स्टेनली ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के चलते भारत में डिजिटलीकरण बढ़ेगा और अधिक संख्या में लोग ऑनलाइन खरीदारी करेंगे। साथ ही मॉर्गन स्टेलनी ने देश में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए रिलायंस जियो की 4जी दूरसंचार सेवाओं को श्रेय दिया। मॉर्गन स्टेलनी ने 'इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी इन ए पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड' नाम की 53 पन्नों की रिपोर्ट में कहा कि बहुत संभव है कि किराना कारोबार में ऑनलाइन पैठ बढ़ेगी और कई सुपर एप इस प्रक्रिया को गति देंगे। भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों में 30 प्रतिशत लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जबकि यह आंकड़ा चीन में 78 प्रतिशत और अमेरिका में 70 प्रतिशत से अधिक है। मॉर्गन स्टेनली ने अनुमान जताया है कि भारत के 67 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता 2027 तक बढ़कर 91.4 करोड़ हो जाएंगे और ऑनलाइन खरीदारी करने वालों की संख्या 19 करोड़ से बढ़कर 59 करोड़ हो जाएगी। ऑनलाइन खरीदारी के दौरान प्रति उपयोगकर्ता औसत खर्च भी दोगुना होकर 318 डॉलर होने का अनुमान है। मॉर्गन स्टेनली ने कहा, "रिलायंस जियो की 4जी दूरसंचार सेवाओं की सितंबर 2016 में शुरुआत होने से भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी आई। इससे तेज, भरोसेमंद, सस्ती 4जी सेवाओं का विकल्प मिलने से डाटा का इस्तेमाल बढ़ा।" मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि कोविड-19 ने डिजिटल लेनदेन से संबंधित कुछ आशंकाओं को दूर किया है और इससे भारत में ऑनलाइन लेनदेन (जैसे ई-कॉमर्स और भुगतान) में तेजी आ सकती है।

आरोग्य सेतु ऐप में खामी ढूंढने वाले को बड़ा इनाम देगी सरकार

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु में निजता को लेकर उठाई जा रही चिंताओं को देखते हुए मंगलवार को इसके स्रोत कोड का सॉफ्टवेयर विकसित करने वाले समुदाय की ओर से जांच-परख के लिए खोलने की घोषणा की। सरकार ने इसके साथ ही इसमें खामियों का पता लगाने वाले को बड़ी राशि का पुरस्कार देने का भी ऐलान किया है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि दुनिया में कोई भी अन्य सरकार इस पैमाने पर इतना खुला रुख नहीं अपनाती है। कोरोना वायरस महामारी से लोगों को सतर्क करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप की शुरुआत की गई। लेकिन कुछ लोगों ने इस ऐप के जरिए लोगों के निजी डेटा जुटाए जाने और उनकी निजी जिंदगी के बारे में तांकझांक करने का आरोप लगाया। सरकार ने इन्हीं चिंताओं का समाधान करने के लिए यह कदम उठाया है। इस ऐप के स्रोत कोड को खोल दिया गया है। कांत ने कहा, 'पारदर्शिता, निजता और सुरक्षा ही आरोग्य सेतु डिजाइन के मूल सिद्धांत हैं। इसके स्रोत कोड को डेवलपर समुदाय के लिए खोल दिये जाने से भारत सरकार की इन सिद्धांतों के दायरे में रहते हुए काम करने की प्रतिबद्धता का पता चलता है। दुनिया में कहीं भी कोई अन्य सरकार स्रोत को इतने बड़े पैमाने पर नहीं खोलती है।' नैशनल इन्फोमेटिक सेंटर की महानिदेशक नीता वर्मा ने कहा कि इस ऐप में खामी का पता लगाने वाले लोगों के लिए चार श्रेणी के पुरस्कार रखे गए हैं। इसमें खामी का पता लगाने और इसके कार्यक्रम सुधार के सुझाव देने वालों के लिए यह पुरस्कार रखे गए हैं। वर्मा ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशीलता को लेकर तीन श्रेणियों में प्रत्येक में एक लाख रुपये का पुरस्कार रखा गया है, जबकि कोड में सुधार के सुझाव के लिए एक पुरसकार एक लाख रुपये का रखा गया है। आरोग्य सेतु ऐप 2 अप्रैल, 2020 को जारी की गई और इसके वर्तमान में करीब 11.5 करोड़ लोग इस्तेमाल करने वाले हैं।

Aarogya Setu
मैं सुरक्षित | हम सुरक्षित | भारत सुरक्षित

कारोबार के डिजिटल होने के साथ ही साइबर सुरक्षा को लेकर अधिक सावधानी जरूरी: डब्ल्यूईएफ

नयी दिल्ली। एजेंसी

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी के चलते व्यक्ति, संगठन और वैश्विक अर्थव्यवस्था कारोबार करने के लिए इंटरनेट और डिजिटल तौर-तरीकों पर अत्यधिक निर्भर हो गए हैं और ऐसे में साइबर हमले और डाटा धोखाधड़ी से निपटने के लिए तत्काल कार्य योजना बनाने की जरूरत है। डब्ल्यूईएफ ने मंगलवार को कहा, "एक ऐसे माहौल में जहां गति ही सबकुछ है और जहां मुख्य निर्णयों में देरी का कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है, वहां प्रत्येक संगठन सीखने और बदलाव की सीमित क्षमता के साथ कोविड-19 का मुकाबला कर रहा है।" रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल दायरे में अचानक हो रहे बदलावों के साथ ही इन कंपनियों और देशों को महत्वपूर्ण प्रणालियों की संवेदनशीलता के बारे में जागरूक करना जरूरी है, जिस पर वे निर्भर हैं और जिन्हें अधिक सुरक्षित होना चाहिए। जिनेवा स्थित डब्ल्यूईएफ ने कहा कि कोविड-19 के चलते डिजिटल निर्भरता अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है, और इसके साथ ही साइबर जोखिमों और कमजोरियों का सामना भी हमें करना है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के लिए कोविड-19 के तकनीकी जोखिमों में साइबर सुरक्षा और डाटा धोखाधड़ी प्रमुख हैं। डब्ल्यूईएफ ने कहा कि उसने कारोबारियों के लिए साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के पांच सिद्धान्त तैयार किए हैं। ये सिद्धान्त हैं- साइबर लचीलापन की संस्कृति को बढ़ावा देना, संगठन की महत्वपूर्ण संपत्ति और सेवाओं की सुरक्षा, संकट के दौरान और बाद में संतुलित निर्णय, नवीनतम तथा आजमाई हुई प्रतिक्रिया और व्यापार निरंतरता योजना। डब्ल्यूईएफ ने कहा कि ये सिद्धांत इस महत्वपूर्ण अवधि में जिम्मेदारी भरा निर्णय लेने और कार्रवाई करने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं।

भारत देख रहा अब तक की सबसे भीषण मंदी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी 10% ग्रोथ!

नई दिल्ली। एजेंसी

रेटिंग एजेंसी एंजेसी क्रिसिल का कहना है कि भारत अब तक की सबसे खराब यानी भीषण आर्थिक मंदी की स्थिति का सामना कर रहा है। क्रिसिल के अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ में कुल 5 फीसदी तक गिरावट आ सकती है। सबसे खराब स्थिति चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में होगी। इस दौरान जीडीपी ग्रोथ में 25 फीसदी बड़ी गिरावट आ सकती है। इधर एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही यानी जनवरी से मार्च-2020 के दौरान देश की ग्रोथ रेट 1.2 फीसदी रहने का अनुमान है। स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो सरकार इस साल के अंत तक एक और आर्थिक पैकेज ला सकती है। गौरतलब है कि आरबीआई पहले ही कह चुका है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव जोन में जा सकती है।

क्रिसिल ने मंगलवार को कहा कि भारत अब तक की सबसे खराब मंदी की स्थिति का सामना कर रहा है। आजादी के बाद यह चौथी और उदारीकरण के बाद पहली मंदी है और यह संभवतः सबसे भीषण है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार कोविड - 19 संकट और लॉकडाउन से चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 5 प्रतिशत की गिरावट आने की आशंका है। चालू वित्त वर्ष पहली तिमाही, अप्रैल से जून में ग्रोथ रेट 25 प्रतिशत की बड़ी गिरवट की आंशका है। अगर तकनीकी तौर पर देखा जाए तो यह नुकसान इतना बड़ा है कि करीब 10 प्रतिशत जीडीपी स्थायी तौर पर खत्म हो सकती है। ऐसे में हमने महामारी से पहले जो ग्रोथ रेट देखी है, अगले तीन वित्त वर्ष तक उसे देखना या हासिल करना मुश्किल होगा।

रोजगार पर असर

क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। न केवल गैर कृषि कार्यों बल्कि शिक्षा, यात्रा और पर्यटन समेत अन्य सेवाओं के लिहाज से पहली तिमाही बदतर रहने की आशंका। इसका प्रभाव आने वाली तिमाहियों पर भी दिखेगा। नौकरियों और आय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा क्योंकि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को कामकाज मिला हुआ है।

जनवरी-मार्च तिमाही पर भी असर

एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार अंतिम तिमाही के दौरान 1.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जीडीपी ग्रोथ पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में 4.2 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2020-21 में नकारात्मक 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) 29 मई को वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों की घोषणा करेगा। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट घटकर सात साल के निचले स्तर 4.7 प्रतिशत पर आ गई थी।

मर्सडीज बेंज ने भारत में पेश की एएमजी सी63 कूपे, एएमजी जीटी आर कूपे

मुंबई। एजेंसी

महंगी कार बनाने वाली जर्मनी की कंपनी मर्सडीज-बेंज ने बुधवार को अपनी एएमजी सी63 कूपे और एएमजी जीटी आर कूपे भारतीय बाजार में पेश की। केरल को छोड़कर अन्य शहरों में इसकी शोरूम कीमत 1.33 करोड़ रुपये से 2.48 करोड़ रुपये के बीच है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस नयी पेशकश के साथ मर्सडीज बेंज इंडिया को लक्जरी कार बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है। पिछले साल लक्जरी बाजार में 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी। कंपनी ने कहा कि इस पेशकश के साथ इस बाजार में उसके पास सबसे अधिक 15 मॉडल हैं। कंपनी के भारतीय परिचालन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्टिन श्वेंक ने कहा कि बाजार में मजबूत पकड़, प्रतिबद्ध खुदरा नेटवर्क और लक्जरी कारों के ज्यादा मॉडलों के साथ हमारी एएमजी वाहनों को पेश करने की रणनीति हमें घरेलू बाजार में लक्जरी कार श्रेणी में अग्रणी बनने में करेगी।''

देश में सस्ता हुआ एन-95 मास्क सरकारी हस्तक्षेप के बाद कीमतें घटीं

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने कहा कि एन-95 मास्क बनाने वाली प्रमुख कंपनियों और आयातकों ने इसके दाम 47 प्रतिशत तक कम कर दिए हैं। नियामक राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) के देश में इस प्रमुख उत्पाद को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाने के बाद कीमतें नीचे आई हैं। बाजार में पहले एन-95 मास्क प्रति इकाई 150 से 300 रुपये में बेचे जा रहे थे। एनपीपीए के परामर्श के बाद इसी कीमत कम हुई हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि एन-95 मास्क की ऊंची कीमत के मसले के समाधान के लिए एनपीपीए ने कदम उठाया और यह सुनिश्चित किया कि वह देश में आम लोगों को सस्ती दर पर उपलब्ध हो। बयान के अनुसार, 'प्राधिकरण ने 21 मई 2020 को सभी विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को परामर्श जारी कर एन-95 मास्क की गैर-सरकारी खरीद के लिए मूल्य एकसमान और युक्तिसंगत रखने को कहा था।' एनपीपीए ने बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष भी कहा कि वह देश में एन-95 मास्क की मांग और आपूर्ति में अंतर को देख रहा है और विनिर्माताओं, आयातकों तथा आपूर्तिकर्ताओं को स्वेच्छा से इसके दाम कम करने की सलाह दी है। उच्च न्यायालय के कोरोना संक्रमण से बचाव के इस महत्वपूर्ण उत्पाद के दाम तय करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने यह बात कही। बयान के अनुसार परामर्श जारी करने के बाद एन-95 मास्क के दाम में 47 प्रतिशत तक की कमी आई है। सरकार ने एन-95 मास्क को अनिवार्य वस्तु अधिसूचित किया है और इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत रखा है।

इकॉनमी को रफ्तार देने के लिए सिस्टम में और नकदी की जरूरतः गडकरी

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बाजार में और नकदी डालने की जरूरत है और राज्य सरकारों को 20 लाख करोड़ रुपये मुहैया कराने चाहिए, जबकि और 10 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक-निजी साझेदारी के निवेश से आ सकते हैं। सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं सूक्ष्म-मध्यम-लघु उद्योग (एमएसएमई) मंत्री ने कहा कि इससे केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज सहित 50 लाख करोड़ रुपये की तरलता बाजार में आएगी, जिससे अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की वजह पड़े विपरीत असर का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, 'मौजूदा परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। पूरी दुनिया मुश्किलों का सामना कर रही है।' मंत्री ने रेखांकित किया कि संकट से मुकाबले के लिए अमेरिका ने दो लाख करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है, जबकि जापान ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 12 प्रतिशत के बराबर पैकेज की घोषणा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पैकेज जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर है। गडकरी ने कहा, 'कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब और अधिक संसाधन जुटाए जा सकते हैं और राज्य और 20 लाख करोड़ रुपये का बजट मुहैया करा सकते हैं और न्यूनतम 10 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक निजी निवेश से आ सकते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में 50 लाख करोड़ रुपये आने से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।।'

टूरिज्म, एंटरटेनमेंट और होटल सेक्टर में लाखों जॉब्स दांव पर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार के 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में कुछ भी राहत न पाने से नाराज ट्रैवल ऐंड टूरिज्म, रेस्टॉरेंट और होटल और एंटरटेनमेंट सेक्टर ने सरकार से कहा है कि कुछ और नहीं तो उन्हें एक साल का टैक्स हॉलिडे और सॉफ्ट लोन की सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर इन सेक्टरों पर बड़ी संख्या में नौकरियां जाने की आशंका है। इससे कोविड-19 संकट और लॉकडाउन के माहौल में देश में बेरोजगारी और बढ़ सकती है। इन तीनों सेक्टरों के दिग्गजों ने सरकार से कहा है कि उसने राहत पैकेज की जो घोषणा की है, उसमें उनके लिए कुछ नहीं है। इनका कहना है कि कई कारोबार लॉकडाउन 4.0 में भी नहीं खुल पाए हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह बंद है। रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलिवरी की छूट मिली है। मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत नहीं है। सैलून, वेलनेस सेंटर बंद पड़े हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों का कामकाज ठप पड़ा है। ऐसे में काम बंद होने से बड़ी संख्या में नौकरियां जाने की आशंका है।

पैकेज न मिला तो लाखों के जॉब जाएंगे

ट्रैवल एजेंट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ज्योति मायल का कहना है कि इस वक्त टूर और ट्रैवल्स से जुड़ी कंपनियों की हालत काफी खराब है। सरकार को कुछ तो राहत देना चाहिए। इधर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) का कहना है कि राहत पैकेज नहीं मिला तो केवल ट्रैवल ऐंड टूरिज्म सेक्टर से ही लाखों लोग बेरोजागर हो सकते हैं।

टूरिज्म इंडस्ट्री में 20 लाख नौकरियों पर खतरा

CII की रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 संकट का सबसे ज्यादा घातक हमला ट्रैवल ऐंड टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ा। टूरिज्म इंडस्ट्री की साइज 18 लाख करोड़ रुपये की है। कोरोना से पहले ट्रैवल ऐंड टूरिज्म सेक्टर में 5.5 करोड़ कर्मचारी थे। कोरोना संकट के चलते इस इंडस्ट्री में करोड़ों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। इसी तरह देश में रेस्टॉरेंट सेक्टर की साइज 4.2 लाख करोड़ रुपये का है। कोरोना से पहले इस सेक्टर में 73 लाख कर्मचारी थे, जिनमें से 20 लाख नौकरियां जाने का अनुमान है।

फूड डिलिवरी, एंटरटेनमेंट और वेलनेस जॉब्स पर कितना खतरा?

इसी तरह ऑनलाइन फूड डिलिवरी सेक्टर की साइज 48,000 करोड़ रुपये है। इसमें कुल कर्मचारी करीब 5 लाख हैं। इस कारोबार के इनकम में 20 फीसदी गिरावट संभव है। सिनेमा, एंटरटेनमेंट की बात करें तो इसकी साइज 1.82 करोड़ रुपये है। कुल कर्मचारी 70 से 80 लाख हैं। इसी तरह देश में सैलून, ब्यूटी, वेलनेस इंडस्ट्री की साइज 1 लाख करोड़ रुपये है। इसमें कुल 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं, इवेंट इंडस्ट्री की साइज 10,000 करोड़ रुपये की है। यह 3 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। कोरोना की वजह से इस सेक्टर में 90 फीसदी कारोबार खत्म हो गया है।

टैक्स हॉलिडे की मांग

तीनों सेक्टर ने सरकार से कहा है कि उनको सभी तरह के टैक्स पर 1 साल का टैक्स हॉलिडे मिलना चाहिए। इनकम टैक्स रिफंड तुरंत मिले। इंडस्ट्री के लिए 10 साल के लिए सॉफ्ट लोन की व्यवस्था की जाए। टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स (ऊण्ए) हटाया जाए और ब्याज चुकाने के लिए 9 महीने की मोहलत मिले। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े सुनील गुप्ता ने बताया कि सितंबर तक पर्यटकों के आने की कोई उम्मीद नहीं है।

स्कंद पुराण की 5 काम की बातें

हिंदू धर्म ग्रंथों में स्कंदपुराण को महापुराण कहा जाता है। पुराणों के क्रम में इसका तेरहवां स्थान है इसके खंडात्मक और संहितात्मक उपलब्ध दो रूपों में से प्रत्येक में 81 हजार श्लोक हैं। इस पुराण का नाम भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय के नाम पर है। कार्तिकेय का ही नाम स्कन्द है। यह शैव संप्रदाय का पुराण है जिसमें स्कन्द द्वारा तारकासुर के वध की कथा का वर्णन मिलेगा। इस पुराण में काशीखंड, महेश्वर खंड, रेवाखंड, अवन्तिका खण्ड, प्रभास खण्ड, ब्रह्म खण्ड और वैष्णव खण्ड आदि कुल सात खंड है। कुछ विद्वान छह खंड बताते हैं। इसमें सती दाह, समुद्र मंथन, तारकासुर वध, शक्तिपीठ, 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों, गंगा अवतरण सहित पर्वत श्रृंखलाओं के उल्लेख के साथ ही सोमदेव, तारा, उनके पुत्र बुध की उत्पत्ति की कथा का वर्णन भी मिलती है। इसके अलावा स्कंद पुराण में धर्म ज्ञान और नीतियों से संबंधित कई बातें बताई गई हैं। आओ जानते हैं स्कंद पुराण की 5 खास बातें।

1. शंकरजी होते हैं प्रसन्न : स्कंद पुराण का पाठ करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण की महाकाल कथा में इसका वर्णन मिलता है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति का वर्णन भी है।

2. प्रदोष व्रत का महत्व : स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत के महामात्य का वर्णन मिलता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें एक विधवा ब्राह्मणी और शांडिल्य ऋषि की कथा के माध्यम से इस व्रत की महिमा का वर्णन मिलेगा।

3. गृहस्थ जीवन :

जीवितं च धनं दारा पुत्राः क्षेत्र गृहाणि च। याति येषां धर्मार्कृते त भुवि मानवाः स्कंदपुराणः.

अर्थात- मनुष्य जीवन में धन, स्त्री, पुत्र, घर-धर्म के काम, और खेत– ये 5 चीजें जिस मनुष्य के पास होती हैं, उसी मनुष्य का जीवन इस धरती पर सफल माना जाता है।

4. वैशाख मास का महत्व : स्कंद पुराण के वैष्णव खंड अध्याय 4 में वैशाख मास के महामात्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके श्लोक 34 के अनुसार इस मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दो बार भोजन करना, रात में खाना आदि वर्जित माना गया है। वैशाख के माह में पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। स्कंदपुराण में उल्लेख है कि महीरथ नाम के राजा ने केवल वैशाख स्नान से ही वैकुण्ठधाम प्राप्त किया था। इस माह में पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अनाज, जलदान, प्रदोष व्रत, स्कंद पुराण का पाठ करने का महत्व है।

वैशाखे मेषगे भानौ प्रातःस्नानपरायणः ।।

अर्घ्यं तेऽहं प्रदास्यामि गृहाण मधुसूदन ।। 34 ।।

5. श्रद्धा एवं मेधा का महत्व : संक्षिप्त स्कन्दपुराण के वैष्णवखण्ड-कार्तिकमास-माहात्म्य के अनुसार ब्रम्हाजी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर श्रद्धा एवं मेधा ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जो काम, क्रोध आदि का नाश करती हैं।

बुधवार को क्या करें और क्या नहीं, जानिए

बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। ज्योतिष अनुसार यह भगवान गणेश और लाल किताब अनुसार दुर्गा माता का दिन है। कमजोर मस्तिष्क वालों को बुधवार के दिन उपवास रखना चाहिए, क्योंकि बुधवार का दिन बुद्धि प्राप्ति का दिन होता है।

ये कार्य करें :

1. सूखे सिंदूर का तिलक लगाएं।
2. बुधवार को दुर्गा के मंदिर जाना चाहिए।
3. पूर्व, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में यात्रा कर सकते हैं।
4. इस दिन जमा किए गए धन में बरकत रहती है।
5. मंत्रणा, मंथन और लेखन कार्य के लिए भी यह दिन उचित है।
6. ज्योतिष, शेयर, दलाली जैसे कार्यों के लिए भी यह दिन शुभ माना गया है।
7. मंदिर के बाहर बैठी किसी कन्या को बुधवार के दिन साबुत बादाम देना चाहिए। इससे घर की बीमारी दूर होती है।

ये कार्य न करें :

1. उत्तर, पश्चिम और ईशान में यात्रा न करें।
2. बुधवार को करें हरी सब्जी का त्याग।
3. बुधवार को धन का लेन-देन नहीं करना चाहिए।
4. बुधवार को लड़की की माता को सिर नहीं धोना चाहिए, ऐसा करने से लड़की का स्वास्थ्य बिगड़ता है या उसके समक्ष कोई कष्ट आता है।

न केवल शास्त्र बल्कि विज्ञान के अनुसार भी चरण स्पर्श है पुण्य वर्धक

हमारे भारतीय समाज में परिवार के बड़े बुजुर्गों तथा संत महात्माओं का चरणस्पर्श करने की परम्परा प्राचीनकाल से चली आ रही है। इस परम्परा के पीछे अनेक कारण मौजूद हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि वरिष्ठ वयोवृद्ध जन के चरण स्पर्श से हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है। उनके शुभाशीर्वाद से हमारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है तथा मन को शांति मिलती है। बड़ों का चरण स्पर्श अथवा प्रणाम एक परम्परा या विधान नहीं है अपितु यह एक विज्ञान है जो हमारे मनोदैहिक तथा वैचारिक विकास से जुड़ा है। इससे हमारे मन में अच्छे संस्कारों का उदय होता है तथा नई पुरानी पीढ़ी के बीच स्वस्थ सकारात्मक संवाद की स्थापना होती है। चरण स्पर्श, प्रणाम-निवेदन करना अभिवादन भारतीय सनातन शिष्टाचार का महत्वपूर्ण अंग है, यह एक जीवन संस्कार है। प्रणाम-निवेदन में नम्रता, विनयशील, श्रद्धा, सेवा, आदर एवं पूज्यता का भाव सन्निहित रहता है। अभिवादन से आयु, विद्या, यश, एवं बल की वृद्धि होती है। भारतीय परम्परा

में प्रातः जागरण से शयन पर्यन्त प्रणाम की अविछिन्न परम्परा प्रवाहमान रहती है। प्रातः का दर्शन भूमि वन्दन से लेकर शयन से पूर्व ईश विनय तक सबमें अभिवादन का भाव शामिल रहता है। बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श तीन प्रकार से किया जाता है (1) झुक कर, (2) घुटनों के बल बैठ कर (3) साष्टांग प्रणाम कर।

इनसे जो आध्यात्मिक लाभ होता है, वह तो है ही, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी प्रणाम की प्रक्रिया अत्यन्त लाभदायक है। पहली विधि यानी झुककर चरण स्पर्श करने से कमर और रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। दूसरी विधि से शरीर के सारे जोड़ों को मोड़ा जाता है जिससे उनमें होने वाले दर्द से राहत मिलती है। तीसरी विधि से चरण स्पर्श करने यानि साष्टांग प्रणाम करने से शरीर के सारे जोड़ थोड़ी देर के लिए तन जाते हैं तथा इससे तनाव दूर होता है। इसके अलावा प्रथम विधि द्वारा चरण स्पर्श में झुकना पड़ता है। झुकने से सिर में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है जो स्वास्थ्य, खास तौर पर नेत्रों के लिए लाभकारी है। द्वितीय तथा तृतीय विधि से चरण स्पर्श करने से स्वास्थ्य लाभ होता है और अनेकों रोगों को दूर करने में सहायक है। चरण स्पर्श से मन का अहंकार समाप्त होता है तथा हृदय में समर्पण और विनम्रता का भाव जागृत होता है इसलिए भारतीय संस्कृति में बड़ों के सादर चरण स्पर्श की पुरातन परम्परा है।

अभिवादन की श्रेष्ठतम विधि साष्टांग प्रणाम है। पेट के बल भूमि पर दोनों हाथ आगे फैलाकर लेट जाना साष्टांग प्रणाम है। इसमें समस्त भ्रूमध्य नासिका वक्ष, ऊरू, घुटने, करतल तथा पैरों की उंगलियों का ऊपरी भाग-ये आठ अंग भूमि से स्पर्श करते हैं और फिर दोनों हाथों से सामान्य पुरुष का चरण स्पर्श किया जाता है। एक हाथ से प्रणाम आदि करना शास्त्र-निषेध है। वास्तव में प्रणाम देह को नहीं अपितु देह में स्थित सर्वान्तर्यामी पुरुष को किया जाता है।

घोड़े का स्टेच्यू घर में रखने से मिलती है कामयाबी

दुनिया का हर इंसान व्यापार में तरक्की चाहता है। बहुत से लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती है जिसके चलते वह टोने और टोटके का सहारा भी लेता है। आज हम आपको वास्तु में बताए गए उपायों के बारे में बताने जा रहे है जिन्हें आजमाने के बाद आपके कारोबार में न सिर्फ तरक्की होगी बल्कि आप अमीर भी बन जाएंगे।

जीवन में बार-बार परेशानियां और रुकावटें

यदि आपके जीवन में बार-बार परेशानियां और रुकावटें आती रहती हैं, तो आप फेंगशुई शास्त्र की मदद से इसमें काफी हद तक परिवर्तन ला सकते हैं यानी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और परेशानियों से भी निजात पा सकते हैं।

राशियों में घोड़े को सातवां स्थान

फेंगशुई शास्त्र में बारह राशियों में घोड़े को सातवां स्थान प्राप्त है और यही कारण है कि इसे काफी अहम माना जाता है। यदि अपने बेडरूम में घोड़ा रखना चाहते हैं तो उसे हमेशा जोड़े में ही रखें। ऐसा माना गया है कि घोड़े का जोड़ा रखने से पति-पत्नि के बीच प्रेम बढ़ता है। घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है।

घोड़ा स्फूर्ति और तेजी का एहसास कराने वाला

फेंगशुई शास्त्र में बताया गया है कि ऑफिस में अपने कारोबार के हिसाब से इसे जगह देना चाहिए और अगर आप अकेले कारोबार संभालते हैं तो फिर एक ही घोड़ा काफी है लेकिन अगर समूह के साथ व्यापार संचालित हैं तो यह संख्या ज्यादा हो सकती है।

टिड्डी दल

कोरोना वायरस के बाद अब भारत पर एक और हमला!

'आतंक' के साए में किसान

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस महामारी के बाद, एक और बिन बुलाया मेहमान भारत के लिए सिरदर्द बन गया है। ये हैं दुनिया के सबसे खतरनाक प्रवासी कीट टिड्डे। टिड्डियों के एक बड़े दल ने अप्रैल में पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किया और ये तब से ये फसलों को चट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 26 सालों में भारत पर ये टिड्डी दल का सबसे खतरनाक हमला है।

यह टिड्डी दल अफ्रीका के सींग से फैलकर यमन तक गया, फिर ईरान और पाकिस्तान. पाकिस्तान में कई हेक्टेयर में फैले कपास के खेतों पर हमला करने के बाद इन्होंने भारत को निशाना बनाया। एक अकेला दल एक वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हो सकता है। 8 से 15 करोड़ के करीब टिड्डियां 35,000 से ज्यादा लोगों के लिए पर्याप्त फसल को तबाह कर सकती हैं।

इनके पास प्रजनन करने की असाधारण क्षमता होती है, और ये लंबी उड़ान भरने में माहिर होती हैं। एक ही दिन में, ये करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। सर्दियों से ही इन कीटों ने किसानों के रातों की नींदें हराम कर रखी हैं।

पिछले एक साल में, टिड्डियों से प्रभावित ज्यादातर खेतों में एक तिहाई से अधिक फसल बर्बाद हो चुकी है। ये गर्मियों की फसल खाने के लिए अक्सर जून के आसपास भारत आते हैं, लेकिन इस साल ये अप्रैल में आ गए।

इसने कई राज्यों की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्थाओं को खतरे में डाल दिया है और टिड्डी दल के हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं है। कीटनाशकों से भरे ट्रकों को देश के अलग-अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है लेकिन इन कीटों को केवल रात में ही नष्ट किया जा सकता है जब वे पेड़ों पर आराम करते हैं।

इस समस्या से लड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये तेज गर्मियों से लेकर सर्दियों तक टिड्डियां प्रजनन कर सकती हैं। इन्होंने अफ्रीका से लेकर पश्चिम एशिया तक पूरी दुनिया की यात्रा की है। जून 2019 में टिड्डियां ईरान से पाकिस्तान पहुंची थीं, जहां उन्होंने कपास, गेहूं और मक्का जैसी गर्मियों की फसलों को बर्बाद कर दिया था। हालांकि टिड्डी दल के हमले कम होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और टिड्डियां ठहरीं और फैल गईं।

दुनिया के सबसे गरीब देश इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। टिड्डियों ने पूर्व और पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण और पश्चिम एशिया और भारत में खाद्य सुरक्षा और लोगों के लिए आजीविका का खतरा पैदा कर दिया है। भारत, ईरान और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रयास कर रहा है ताकि टिड्डियों के नए दलों को बढ़ने से रोका जा सके।

भारत के लिए यह एक राष्ट्रीय आपदा है। इतिहास में टिड्डियां देश के लिए संकट लेकर आईं, लेकिन 1962 के बाद भारत ने इनका कोई पूर्ण विकसित चक्र नहीं देखा। इस समस्या को आसानी से दूर नहीं किया जा सकता और इसपर कोरोना वायरस की तरह ही ध्यान देने की आवश्यकता है।

अप्रैल में प्रमुख बंदरगाहों से माल ढुलाई 21 प्रतिशत कम होकर 474 लाख टन

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों के जरिये माल वहन इस साल अप्रैल में साल भर पहले की तुलना में 21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 474.2 लाख टन रहा। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन (आईपीए) ने इसकी जानकारी दी है।आईपीए के हालिया आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख बंदरगाहों के कार्गो में कमी आने का मुख्य कारण कोरोना वायरस महामारी है। इसके कारण जेएनपीटी, चेन्नई, कोच्चि और कामराज जैसे बंदरगाहों से माल ढुलाई में भारी गिरावट आयी है।केंद्र सरकार के नियंत्रण में भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह हैं - दीनदयाल (तत्कालीन कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, मोरमुगांव, न्यू मंगलौर, कोच्चि, चेन्नई, कामराजार (पहले एन्नोर), वी ओ चिदंबरनार, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता (हल्दिया सहित)। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इन 12 प्रमुख बंदरगाहों का सम्मिलित माल 7,050 लाख टन रहा था।आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल माह के दौरान इन 12 प्रमुख बंदरगाहों ने 474.2 लाख टन माल संभाला। यह साल भर पहले के समान माह की तुलना में 21.08 प्रतिशत कम है।इस दौरान चेन्नई से माल ढुलाई 38.17 प्रतिशत गिरकर 24.4 लाख टन, जेएनपीटी 33.97 प्रतिशत कम होकर 39.5 लाख टन, कोच्चि 33.73 प्रतिशत गिरकर 18.7 लाख टन और कामराजार बंदरगाह से आने जाने वाली माल की खेप 30.03 प्रतिशत गिरकर 20.8 लाख टन रही।

मप्रः चना, मसूर और सरसों की खरीद पर 25 क्विंटल की सीमा को हटाया गया

भोपाल। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना वायरस के चलते मध्य प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्र ने चालू रबी विपणन सीजन में चना, मसूर और सरसों का उत्पादन करने वाले किसानों को बड़ी राहत देते हुए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत प्रदेश में प्रति किसान, प्रति दिन 25 क्विटंल खरीद की सीमा को हटा दिया है। इस बारे में प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने केंद्र सरकार से राहत देने का अनुरोध किया था। इसके तहत भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में चना, मसूर, सरसों की प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन अधिकतम उपार्जन सीमा को समाप्त कर दिया है। पटेल ने बुधवार को पीटीआई भाषा को बताया, "इस निर्णय से मध्य प्रदेश के किसानों को तत्काल फायदा होगा क्योंकि किसान अपनी पूरी फसल बेच सकेगा, भले ही यह 25 क्विंटल से अधिक क्यों न हो। इससे किसानों के ईंधन और श्रम की बचत होगी।" अब तक किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते थे और इसमें कई बार वह बिचौलियों को समर्थन मूल्य से कम पर भी फसल बेच देते थे। प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि इससे किसानों को कोरोना महामारी से भी सुरक्षा मिलेगी क्योंकि उन्हें बार-बार बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

रिलायंस का ऑनलाइन किराना स्टोर 'जियोमार्ट' 200 शहरों में पहुंचा

नयी दिल्ली। एजेंसी

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियोमार्ट ब्रांड के तहत अपने ऑनलाइन किराना कारोबार का विस्तार 200 शहरों में किया है। मुकेश अंबानी की कंपनी अब ये सेवा सभी प्रमुख महानगरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता के साथ मैसूरु, बठिंडा और देहरादून जैसे छोटे शहरों में भी उपलब्ध करा रही है। जियोमार्ट ने पिछले महीने यह सेवा पायलट आधार पर शुरू की थी। इसके तहत वह मुंबई के आसपास के तीन इलाकों में सेवाएं दे रही थी। क्रेडिट सुइस ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जियोमार्ट की सेवाएं शुरू होने से ग्राहकों को बिगबास्केट और ग्रॉफर्स जैसे कंपनियों का विकल्प मिल गया है। क्रेडिट सुइस ने कहा कि डी-मार्ट की अप्रैल की आय में 45 प्रतिशत की कमी आई है। लॉकडाउन की वजह से कंपनी के करीब 50 स्टोर बंद रहे या उन्हें कुछ घंटों के लिए ही खोलने की अनुमति मिली। ऐसे में स्टोरों पर बिक्री घटी है, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डरों में तेजी आई है। सीएलएसए ने कहा कि यह वेबसाइट अभी घरों तक आपूर्ति के रिलायंस की ऑफलाइन किराना आपूर्ति श्रृंखला का इस्तेमाल करेगी। जियोमार्ट की वेबसाइट पर ग्राहक सभी किराना उत्पादों, फल-सब्जियों, डेयरी और बेकरी उत्पादों, स्नैक्स और बेवरेजेज का ऑर्डर दे सकते हैं। रिलायंस के प्राइवेट लेबल भी उपलब्ध होंगे।

मलेशिया, इंडानेशिया के साथ खाद्य तेल समझौता समाप्त भारत को अब आयात शुल्क बढ़ाना चाहिएः एसईए

नयी दिल्ली। एजेंसी

सोल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) ने सोमवार को कहा कि भारत का मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ 2010 से जारी खाद्य तेल समझौता समाप्त हो गया है, ऐसे में सरकार को सोया, सूरजमुखी और कच्चे पॉम तेल पर सीमा शुल्क बढ़ाना चाहिए और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए।साथ ही एसईए ने सरकार से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये रिफाइंड पॉम तेल या पॉमोलीन के आयात पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया है। उद्योग संगठन ने देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कुछ अल्पकालीन सुझाव सरकार को दिये हैं। एसईए के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने एक बयान में कहा, "...कोई भी देश अपनी सालाना खपत के करीब 70 प्रतिशत के बराबर आयात कर अपनी खाद्य तेल सुरक्षा से समझौता करने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह स्थिति प्राथमिक आधार पर सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत को रेखांकित करता है।" उन्होंने कहा कि पिछले कई साल से खाद्य तेलों पर कम आयात शुल्क से हमारे किसानों की तिलहन की खेती में रूचि कम हुई है। इसमें कोई अचंभा नहीं होगा कि देश का तिलहन उत्पादन स्थिर रहे लेकिन समृद्धि के साथ खाद्य तेल की खपत में तीव्र वृद्धि हो और इसमें सालाना तीन से चार प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है।" हालांकि उन्होंने कहा कि पिछले कुछ साल से इस विसंगति को दूर करने का प्रयास हो रहा है। चतुर्वेदी ने कहा कि भारत ने इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ 2010 में जो समझौता किया था, उससे हमारी सरकार को शुल्क बढ़ाने की अनुमति नहीं थी लेकिन अच्छी खबर यह है कि समझौते की अवधि अब समाप्त होने वाली है और भारत शुल्क दरें बढ़ाने को स्वतंत्र है। एसईए ने सरकार से सोया और सूरजमुखी पर आयात शुल्क मौजूदा 37.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत जबकि कच्चे पॉम तेल पर 50 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। साथ ही संगठन ने रिफाइंड पॉम तेल या पॉमोलीन के आयात पर पूर्ण पाबंदी लगाने को कहा है। चतुर्वेदी ने कहा, "हमारा मानना है कि उक्त उपायों से स्थानीय तौर पर तिलहन की कीमतें बढ़ेंगी, इससे हमारे तिलहन की खेती करने वाले किसान इसका उत्पादन बढ़ाने को लेकर प्रेरित होंगे। साथ ही इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा।" उन्होंने कहा कि रिफाइंड पॉम ऑयल पर पाबंदी से भारतीय रिफाइनिंग उद्योग को इस मुश्किल समय में नौकरियां बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पॉम रिफाइनिंग उद्योग में क्षमता उपयोग फिलहाल 30 प्रतिशत है और मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि की आशंका पूरी तरह निराधार है। एसईए ने बिना किसी देरी के 'ऑयलसीड मिशन' भी शुरू करने और इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को आने की अनुमति देने की वकालत की। संगठन ने दीर्घकालीन उपायों के रूप में सरकार को पंजाब और हरियाणा के किसानों को खरीफ मौसम में सूरजमुखी और रबी मौसम में सरसों की खेती के लिये प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया है।

Authorised Dealer of

Reliance
POLYMERS

Bhaskar Resins Pvt Ltd

DEALER : RELIANCE INDUSTRIES LTD

44 D-2, Sanwer Road Industrial Area, Sector D, Railway Crossing Main Rd, Indore, Madhya Pradesh 452015
website- http://bhaskarresins.com
email- bhaskarresins12@gmail.com

Mob- +91-96307-98864
Tel : 0731 -2971277, 2971377
email- sachinbansal123@gmail.com

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।